Shri S. K. Patil: This question has often been replied to. I think the total is somewhere about 1 million acres, but I have no figures with me just now, because that was not the main question.

Shri Jaipal Singh: May I know how many irrigation canals are there in Bihar and what is the total potential acreage for irrigation purposes?

Mr. Speaker: Under the D.V.C. or generally?

Shri Jaipal Singh: By the D.V.C. canal at Durgapur only Bengal is going to benefit.

Mr. Speaker: The D.V.C. canal does not benefit any portion of Bihar?

Shri Jaipal Singh: You know only too well, Sir, that in the debates we had been asking why what was first planned was converted into something else......

Shri S. K. Patil: The other questions do not arise just now. There is no immediate proposal to have any canals for irrigation. We are trying to see if our reservoirs in Bihar could be better utilised by having some irrigation facilities as well.

Shri Gajendra Prasad Sinha: With the proposal for D.V.C., there was a proposal that an irrigation canal will be provided for Bihar. May I know why this has been changed? What are the main difficulties?

Shri S. K. Patil: It has not been changed, because we are trying and the State Government has been trying hard to find some kind of irrigation facility which is not in expenditure out of proportion. Just now one or two schemes that were placed are so out of proportion in expenditure that it was thought that it was not a feasible proposition to have irrigation at that very high cost.

Shrimati Renu Chakravartty: In view of the fact that the hon. Minister has said that Rs. 4 crores will be needed for the excavation of this inland water channel, may I know whether this money is going to be given from the Central Government as a grant or whether it will be loaded as a loan against West Bengal?

Shri S. K. Patil: This is controlled by the Corporation under a special Act. If the Bengal Government, as the hon. Member says, is to be loaded with it, it will also get the benefit of Rs. 30 lakhs annual income that it will produce.

द्विभाषी टेलीप्रिंटर

\+

*१०५३. { श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ३ दिसम्बर १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अंग्रेजी और हिन्दी के द्विभाषी टेलीप्रिन्टर की उपयोगिता की जांच कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं, और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है ।

(ख) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) लगभग दो महीनों में ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस टेलीप्रिंटर की जांच करते समय शासन की ओर से इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि इस समय जो पांच यूनिट कोड का टेलीप्रिंटर जारी है, उसके

द्वारा देवनागरी लिपि की जितनी भी मात्रायें और दूसरे अक्षर हैं, उनको पूरी तरह से अदा नहीं किया जा सकता है और यदि छ: यूनिट कोड का टेलीप्रिंटर जारी किया गया तो अधिक सुविधा होगी ?

श्री राज बहादुर : जिन विषयों की जांच हो रही है, उन में से एक मुख्य विषय यह भी है कि पांच यूनिट कोड के बजाय छ: यूनिट कोड का टेलीप्रिंटर प्रयोग में लाया जाय ।

श्री जोकिम आल्वा : हिन्दी टेलीप्रिंटर बनाने में कौन सी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्या यह मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राज बहादुर : हिन्दी टेलीप्रिंटर बनाने में तकलीफ यही है कि हिन्दी टेली-प्रिंटर बनाने का जो कारखाना है वह अभी स्थापित करना है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि द्विभाषी टेलीप्रिंटर जो है उसकी क्या कीमत जापानी फर्म ने बताई है और क्या यह सूचित किया है कि अगर बड़ी संख्या में उसको लिया जाएगा तो उसकी कीमत भी घटाई जा सकती है ?

श्री राज बहादुर : क्यों कि अभी यह तय नहीं किया गया है कि उसे लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेना है तो किस किस संख्या में, इसलिए कीमत का सवाल अभी देरी में तय होगा । अभी तक यह भी तय करना है कि जहां तक इंजीनियरिंग या जो ट्रैफिक होता है, उन दोनों के मामले में यह मशीन कहां तक पार उतरती है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सही है कि जो दो टेलीप्रिंटर, एक यहां और दूसरा बम्बई में, चालू किये गए हैं, इन दोनों जगहों से संवाद अच्छी तरह से भेजे जा रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : जी हां, दो मशीनें हैं एक बम्बई में और दूसरी दिल्ली में रखी गई हैं और दोनों के ऊपर इसके परीक्षण हो रहे हैं और अभी तक तो यह कहा जा सकता है कि वे संतोषप्रद हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : द्विभाषी टेलीप्रिंटर के बारे में कितने प्रस्ताव गवर्न-मेंट के पास आए हैं और क्या कलकत्ता से भी कोई आया है ?

श्री राज बहादुर : अगर प्रस्ताव का अर्थ मांग से है तो कितनी मांग इनके बारे में है, इसका पता लगाने में देरी लगेगी ।

श्री हेडा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस जापानी फर्म ने उनके पास अपनी यह जसारी स्कीम भेजी है, उसने कीमत का कोई अंदाजा नहीं दिया है ?

श्री राज बहादुर : कीमत का अंदाजा इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि विभाग के कौन कौन से विशेषज्ञ इसके बारे में जांच कर रहे हैं और क्या इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि संसद् सदस्यों को भी इन दोनों प्रकार के टेली-प्रिंटरों को देखने का मौका मिले ?

श्री राज बहादुर : जहां तक विशेषज्ञों के नामों का सम्बन्ध है, उनके नाम हैं : श्री एस० के० कांजीलाल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ट्रैफिक,

श्री वासुदेवन, जो डायरेक्टर हैं, टेली-कम्युनिकेशन रिसर्च सैंटर के,

श्री एस० एम० अग्रवाल, जो डायरेक्टर आफ टेलीफोन हैं,

श्री जी० बी० मेनन तथा श्री भटनागर आफ दी रिसर्च ब्रांच ।

मुख्य मुख्य बातें जिन पर वे विचार करेंगे वे ये हैं कि कितना खर्चा इस पर लगेगा, किस प्रकार की इसकी स्पीड होगी, अगर एक फैक्ट्री बनाई जाए तो उत्पादन में क्या व्यय होगा और जो वर्तमान में मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं उनका अन्त में क्या किया जाएगा। जहां तक अन्तर्देशीय संचार व्यवस्था का सम्बन्ध है, उसमें पांच यूनिट कोड का प्रयोग किया जाए या छः यूनिट कोड का। ये पांच छः बातें हैं जिनकी इन विशेषज्ञों ने जांच करनी है और वे कर रहे हैं।

Enquiry into Air Crash at Dum Dum

+

*1054. { **Shri D. C. Sharma:**
Shrimati Renu Chakravartty:
Shri H. N. Makerjee:

Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 893 on the 6th December, 1957 and state:

(a) whether Government have since considered the report submitted by the Inquiry Committee appointed to enquire into the death of four members of the crew of an Indian Airlines Corporation freighter Dakota which met with an accident at the Dum Dum airport on the 1st September, 1957; and

(b) if so, the action Government propose to take on it?

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Humayun Kabir): (a) and (b). The Report of the Court of Enquiry is still under examination.

Shri D. C. Sharma: May I know who the members of this court of inquiry were and whether any public man was associated with it.

Shri Humayun Kabir: There was only one High Court judge who constituted the court of inquiry.

Shrimati Renu Chakravartty: Is it a fact that the young widows and the children of these unfortunate victims have not up till now received compensation on the basis of the findings of the court of inquiry?

Shri Humayun Kabir: That is not a fact. Compensation has been paid to three out of the four members. In the case of the fourth member, compensation has not been paid, as no heirs have appeared with any succession certificate.

Shri Joachim Alva: Is it true that between the Dum Dum and the NEFA area the highest number of air accidents has taken place, and if so, have Government gone into the matter to see that these accidents are not repeated hereafter?

Shri Humayun Kabir: This is an entirely different question, but if you ask me, I shall try to answer it.

Mr. Speaker: No.

Shrimati Renu Chakravartty: In view of the fact that this report has been finalised many months ago, and also in view of the fact that the court of inquiry, as far as we have come to know, has found the Hermes's pilot at fault, may I know what the reason for the delay is?

Shri Humayun Kabir: I think both the suggestions of the hon. Member are slightly inaccurate. The report was submitted on 8th October, 1957. There was one technical point on which there was a difference of opinion as to what exactly constituted simultaneous use of parallel runways in an airport, and for this, certain reference had to be made to our representative in the ICAO. I can tell the hon. Member that the final stages have been reached, and perhaps, before the week is out, Government will have to take a decision on the finding of the court. But even then it cannot be released as another Government is concerned; and the practice always is that when Government have accepted the findings, they consult the other Government, and then a date is fixed when the report is simultaneously published.